

हमिचल प्रदेश सुखाश्रय अधिनियम, 2023

प्रलिस के लयः

हमिचल प्रदेश सुखाश्रय अधिनियम, 2023

मेन्स के लयः

हमिचल प्रदेश सुखाश्रय अधिनियम, 2023 के लाभ और महत्त्व

चर्चा में क्यों ?

हमिचल प्रदेश ने **अनाथों और वशेष रूप से ज़रूरतमंदों का कल्याण सुनश्चित करने के लयि** सुखाश्रय (राज्य के बच्चों की देखभाल, संरक्षण एवं आत्मनश्भरता) अधिनियम, 2023 पारत कयः है ।

सुखाश्रय अधिनियम, 2023 के मुख्य बढः

परचय :

- यह अधिनियम ऐसे बच्चों जन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, **जनके माता-पता नहीं हैं या माता-पता अक्षम हैं, को अनाथ** के रूप में परभाषत करता है । इसमें ऐसे बच्चे शामिल हैं जनके पास घर नहीं है या जो जबरन शादी, अपराध या नशीली दवाओं के दुरुपयोग के जोखमि में हैं ।
- यह अधिनियम **18-27 वर्ष की आयु के बीच के लाभार्थयों को** व्यावसायक परशक्षण, कौशल वकऱस और अनुशक्षण के साथ समाज के सकरय सदस्य बनने में मदद करने हेतु **वत्तीय तथा संस्थागत लाभ** प्रदान करता है ।
- अधिनियम समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग की सुरक्षा एवं देखभाल सुनश्चित करने की दशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है ।

अधिनियम के तहत लाभ:

- 101 करोड रुपए परविय के साथ मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष बनाया गया है** तथा योजना की देख-रेख के लयि प्रत्येक ज़ल्लि में एक बाल कल्याण समतऱ की स्थापना की जाएगी ।
- इसके तहत अनाथ एवं वशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चे 'राज्य के बच्चे' माने जाएंगे ।
- इसके तहत वत्तीय लाभ में गर्मयों एवं सर्दयों में **5,000 रुपए**, प्रमुख त्योहारों हेतु **500 रुपए** तथा कॉलेज में दैनक खर्च के लयि **4,000 रुपए मासक भत्ता** शामिल है ।
- संस्थागत लाभों में ट्रेन टकऱ और राज्य के भीतर **10 दनऱ के लयि** आवास तथा ITI एवं सरकारी कॉलेजों में लाभार्थयों हेतु छात्रावास शुलक शामिल है ।
- सरकार, शादी के समय तय रकम तथा अपना घर बनाने के लयि तीन बसऱवा ज़मीन प्रदान करेगी ।
- अनाथ जो अपने स्वयं के स्टार्टअप स्थापत करना चाहते हैं, उन्हें उद्यमशीलता की गतवधऱयों को प्रोत्साहत करने हेतु एक सांकेतक कोष प्रदान कयः जाएगा ।
 - पीएच.डी. छात्रों को मासक भत्ता भी मलऱेगा ।

अधिनियम में उल्लखतऱ अन्य सुरक्षा उपाय:

- बाल देखभाल संस्थानों के पूर्व नवऱसयों को 21 वर्ष की आयु तक राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी ।
- प्रत्येक बच्चे और अनाथ का आवरती जमा खाता खोला जाएगा एवं **राज्य सरकार इन खातों में प्रचलतऱ दरों के अनुसार अंशदान** करेगी ।
- बाल कल्याण समतऱ अनाथों की पहचान हेतु **सर्वेक्षण** करेगी एवं ज़रूरतमंद बच्चों की मांगों पर गौर करेगी ।

नोट: कशऱर नयाय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार, देश में अनाथ एवं नरऱशरतऱ बच्चे "देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे" (Children in Need of Care and Protection- CNCP) हैं । अधिनियम के नषऱादन की प्राथमकऱ ज़मऱेदारी राज्यों/संघ राज्य कषेत्रों की है ।

केंद्र सरकार की समान पहल:

■ बाल संरक्षण सेवा (Child Protection Services- CPS) योजना या "मशिन वात्सल्य":

- इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया।
- CPS के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार कठिन परिस्थितियों में बच्चों का स्थितिजन्य विश्लेषण करने के लिये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है।
- इस योजना के तहत देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को बाल देखभाल संस्थानों (Child Care Institutions- CCI) में संस्थागत देखभाल प्रदान की जाती है।
- यह योजना गैर-संस्थागत देखभाल भी प्रदान करती है जिसमें गोद लेने, पालन-पोषण, देखभाल और प्रायोजन (Sponsorship) हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/himachal-pradesh-sukhashraya-act-2023>

